राज्य सरकार और प्राइवेट शुगर मिलों में एग्रीमेंट

UP की शुगर मिलों में आज से पेराई शुरू

[ईटी ब्यूरो *लखनऊ*]

यूपी सरकार और प्राइवेट चीनी मिलों के बीच आखिरकार समझौता हो गया। सरकार ने फैसला किया है कि गन्ना समितियों को कमीशन का भुगतान वह खुद करेगी। इससे सरकारी खजाने पर करीब 500 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इससे पहले सरकार चीनी मिलों को गन्ना क्रय कर और एंट्री टैक्स में छूट दे चुकी है। ये मांगे माने जाने के बाद चीनी मिलें सोमवार से पेराई शुरू करने को तैयार हो गई हैं। सरकार ने जिलाधिकारियों को तत्काल पेराई शुरू कराने का आदेश दिया है।

गन्ना समितियों को मिलेगा कमीशन

रविवार को चीनी मिल असोसिएशन के साथ बैठक के बाद मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने पत्रकारों को बताया कि निजी मिल मालिकों की तीन मुख्य मांगें थीं। इनमें से सरकार ने दो को पहले ही मान लिया था। मिल मालिकों का कहना था चीनी के दाम में गिरावट की वजह से चीनी पर प्रवेश कर और गन्ने पर क्रय कर माफ किया जाए। इसके साथ मिलों ने इस साल गन्ना समितियों को दिया जाने वाला कमीशन राज्य सरकार द्वारा वहन करने की मांग भी रखी थी। तीनों मांगें मान ली गईं।

खजाने पर 879 करोड़ का बोझ

मिलों की मांगे माने जाने से सरकार को कुल 879 करोड़ रुपये का खर्च वहन करना पड़ेगा। इसमें गन्ना क्रय कर पर छूट से सरकार पर 160 करोड़ का बोझ आएगा। मिलों को प्रति क्विंटल दो रुपए की छूट देनी पड़ेगी। इसके साथ ही प्रवेश कर की छूट प्रति क्विंटल 2.74 रुपए के हिसाब से वहन करनी होगी। इसमें कुल 219 करोड़ सरकार पर बोझ पड़ेगा। गन्ना समितियों को देय कमीशन पर भी प्रति क्विंटल 6.40 रुपए अब सरकार को देने पड़ेंगे। इससे सरकार पर कुल बोझ 500 करोड़ आएगा।

मिलें तत्काल देंगी 260 रुपये का भाव

सरकार ने स्टेट एडमिनिस्टर्ड प्राइस (एसएपी) 280 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, लेकिन चीनी मिलें किसानों को तत्काल सिर्फ 260 रुपए प्रति क्विंटल ही भुगतान करेंगी। इसके बाद 20 रुपए प्रति क्विंटल पेराई सीजन के अंत में यानी अप्रैल में मिलेंगे। 260 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान 14 दिन के भीतर करना होगा।

गन्ना उद्योग से 32 लाख किसान

मुख्य सचिव ने बताया कि चीनी उद्योग से करीब 32 लाख से ज्यादा किसान परिवार और दो लाख से ज्यादा श्रमिक परिवार सीधे जुड़े हैं। प्रदेश में 123 चीनी मिलें हैं, जिनमें 99 निजी क्षेत्र की हैं। एक पेराई सीजन में करीब 22 हजार 500 करोड़ रुपए गन्ने के मूल्य के रूप में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निवेश होते हैं। मुख्य सचिव ने बताया कि पिछले सीजन में जहां चीनी के दाम 3600 रुपए प्रति क्विंटल थे, वहीं इस वक्त 2950 रुपए प्रति क्विंटल हैं। उन्होंने बताया कि चीनी मिलें 225 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा देने को तैयार नहीं थीं।

अब नहीं होगी वैधानिक कार्यवाही

मुख्य सचिव ने बताया कि अब सरकार वैधानिक कार्यवाही नहीं करेगी। आरसी जारी होने की कार्यवाही स्थगित रहेगी। हालांकि पुराने बकाया भुगतान को लेकर कार्यवाही जारी रहेगी। चीनी मिलों पर पिछले सीजन के करीब 2 हजार 320 करोड़ रुपये बकाया हैं।

Economic times

2/12/17